

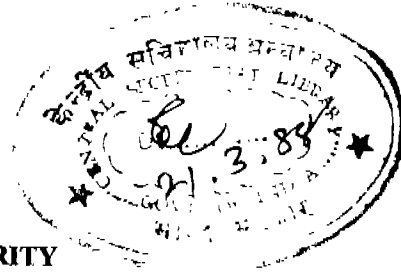


भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 230]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 17, 1987/कासिक 26, 1909

No. 230]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 17, 1987/KARTIKA 26, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 228 आई टी सी (पी एन)/85-88

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1987

विषय :—भारत-स्वीडन विकास सहयोग समझौता—1987
के अधीन निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के
आयातों के संबंध में लाइसेंस शर्तें।

[फाइल सं. आई पी सी 23(39)/85-88 से जारी]
भारत-स्वीडन विकास सहयोग समझौता, 1987 के अधीन
आयातों के संबंध में लागू होने वाली शर्तें जो इस सार्वजनिक
सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं, वे जानकारी के लिए
अधिसूचित की जाती हैं।

ह./—

राजीव लोचन मिश्र
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात
आर. के. धवन,
उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 228 आई
टी सी (पी एन)/85-88, दिनांक 17-11-87 का परिशिष्ट

आमंत्र

भारत-स्वीडन विकास सहयोग समझौता (1987)
के अन्तर्गत स्वीडन सहायता में स्वीडन में खण्ड आयात
शामिल है जो केवल स्वीडन से ही प्रभावी हो सकता है
या उसकी सेवाएं स्वीडन से ही ली जा सकती हैं अर्थात्
माल स्वीडन में ही विनिर्मित होना चाहिये।

आयात-लाइसेंस

1. आयात-लाइसेंस लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर
संविदा करने के लिए 4 महीने की और पोतलदान एवं
भुगतान पूर्ण करने के लिए 12 महीने की प्रारम्भिक वैधता
के साथ जारी किए जाएंगे। सभी पोतलदान लाइसेंस की
वैधता अवधि समाप्त होने के एक महीने के भीतर अवश्य
पूर्ण करने चाहिए।

2. प्रत्येक आयात लाइसेंस पर एक शीर्षक "भारत-
स्वीडन विकास सहयोग समझौता, 1987 स्वीडन से आयात
होगा। लाइसेंस कोड वर्गीकरण संख्या में प्रत्यय

“एस. डब्ल्यू.” होंगे। ये प्रत्यय आयात लाइसेंस भेजते समय मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के पत्र में भी दुहराए जाएंगे।

3. आयात लाइसेंस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर आयातक को आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक और मूल्य तथा सम्भाव्य तिथि, जिन तक संविदा दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे, निर्दिष्ट करते हुए आयात लाइसेंस की प्राप्ति के तत्त्व से अधिक कार्य विभाग (आई. ए. अनुभाग) को सूचित करना चाहिए।

4. जब तक नीचे के पैरा 16 में यथानिर्दिष्ट-4 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर पूर्ण संविदा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे तब तक संविदा करने से सम्बन्धित शर्त का पालन किया गया नहीं माना जाएगा।

5. यदि, इस शर्त का पालन 4 महीने के भीतर नहीं किया जाएगा तो आयात लाइसेंस अवैध हो गया समझा जाएगा।

6. लेकिन, पार्टी द्वारा समय के भीतर शर्त का पालन न करने के कारण देने हुए एक आवेदन-पत्र देने पर आयात लाइसेंस पुनर्वैध किया जा सकता है। पुनर्वैधीकरण के लिए आवेदन पर प्राधिकारी द्वारा गुणों के आधार पर विचार किया जाए और लाइसेंस संविदा के लिए अधिक से अधिक अगले चार महीनों की अवधि के लिए पुनर्वैध किया जाएगा। इस अवधि से आगे किसी प्रकार का पुनर्वैधीकरण कराने के लिए आर्थिक कार्य विभाग (आई. ए. अनुभाग) के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

संविदा करना

7. एक संविदा में सामान्यतः दोनों पार्टियों अर्थात् भारतीय आयातक और विदेशी संभरक द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता शामिल होगा अथवा इसमें भारतीय आयातक द्वारा दिया गया आदेश और विदेशी संभरक द्वारा उस आदेश का स्पष्ट शब्दों में स्वीकृति पत्र हो सकती है। समुद्रपार संभरकों के भारतीय अभिकर्ताओं के लिए आदेश और/या ऐसे भारतीय अभिकर्ताओं द्वारा आदेश का पुष्टिकरण स्वीकार्य नहीं है।

8. दो पार्टियों के बीच विभिन्न शर्तों की बार-बार संशोधित/परिशोधित करने से सम्बन्धित पत्र व्यवहार के अनुक्रम से समाविष्ट संविदा स्वीकृत नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों में, दोनों पार्टियों द्वारा स्वीकृत शर्तों सहित और हस्ताक्षरित दस्तावेज तैयार करना आवश्यक है।

9. सामान्यतः पक्की कीमतों के आधार पर लाइसेंस के पूरे मूल्य के लिए विदेशी संभरक के साथ एक संविदा की जाती है। लेकिन, विशेष कारणों से यदि एक से अधिक संविदा करना आवश्यक हो जाता है तो इसके लिए कारण देते हुए आर्थिक कार्य विभाग की पूर्वअनुमति ले लेनी चाहिए।

संविदा की शर्तें

सामान्य

10. निजी क्षेत्र के आयातकों के लिए यह आवश्यक है कि वे लागत-सीमा-भाड़े या लागत और भाड़े के आधार पर संविदा करें। उन्हें चाहिए कि वे जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य बीमा प्रसार एवं भाड़े को अलग-अलग स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करें।

संविदा सरकारी अभिकरण या सार्वजनिक क्षेत्र संस्थान द्वारा केवल लागत और भाड़ा के आधार पर ही होनी चाहिए।

यदि कोई आयातक जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के आधार पर कोई संविदा करने का इच्छुक है, तो पार्टी को ऐसा करने के लिए कारण देते हुए आर्थिक कार्य विभाग (आई. ए. अनुभाग) वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली का पूर्व अनुमोदन मांगना चाहिए।

11. यदि विदेशी संभरक के भारतीय एजेंट को कोई कमीशन चुकाया जाना है, तो उसे संविदा के मुख्य से अलग दिखाया जाएगा। भारतीय एजेंट का कमीशन भारतीय रुपये में चुकाया जाएगा परन्तु आयात लाइसेंस के कुल मूल्य के प्रति समंजित किया जाएगा।

12. संविदा का मूल्य उसी मुद्रा में व्यक्त होना चाहिए जिसमें विदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है। इन धन-राशियों का रुपये में परिवर्तन सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के खण्ड -15 के अन्तर्गत राजस्व विभाग (सीमा-शुल्क) द्वारा अधिसूचित विनियम की दर पर और आयात लाइसेंस जारी होने की तारीख को परिचालित मुद्रा विनियम की दरों पर किया जाएगा।

संविदाओं की मूल्य सीमाएं

13. प्रत्येक संविदा का मूल्य 75 हजार रुपये के बराबर की धनराशि से कम नहीं होना चाहिए।

माल का उद्गम देश

14. (1) आमुख में उल्लिखित स्वीजन से आयात के मामले में, माल स्वीडन में विनिर्मित होना चाहिए या दी जाने वाली सेवाएं स्वीडन मूल की होनी चाहिए। माल के स्वीडन में विनिर्मित होने के संबंध में या स्वीडन मूल की सेवाओं के संबंध में एक अनुबन्ध समाविष्ट किया जाएगा।

(2) लाइसेंसधारी को नीचे के पैरा 16(3) में उल्लिखित संविदा दस्तावेज प्रस्तुत करते समय प्राप्त की गई बोलियों और विशेष संभरक तथा माल का चुनाव करने के लिए कारणों का एक विवरण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

पोतलदान

15. जहां तक संभव हो, प्रत्येक ऐसे वितरण पोतलदान के महीने को संकेतिक करते हुए संविदा के वितरण/पोत परिवहन संबंधी अनुसूचित विशिष्ट शब्दों में होनी चाहिए।

पोतलदान अनुसूची में बाढ़ में होने वाले किसी व्यक्ति-क्रम से तुरन्त वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, आई ए अनुभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को सूचित करना चाहिए। प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित संविदा प्रलेखों के ब्यौरे :

16. संविदा में तय किए जाने के 20 दिनों के भीतर ही आयातक को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ एक पत्र सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षक नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यूको बैंक बिल्डिंग, पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजना चाहिए :—

- (1) अंग्रेजी भाषा में विधिवत् निर्धारित और भारतीय आयातक तथा विदेशी संभरक, दोनों द्वारा हस्ताक्षरित संविदा की ओर आगे होने वाले किसी प्रकार के संशोधन की चार प्रमाणित प्रतियां।
- (2) संविदा के निष्पादन/आयातक द्वारा दिए गए आदेश की विदेशी संभरक को की गई स्वीकृत/तिथि को संविदा करने के लिए बंध आयात हाईसेंस मुद्रा विनिमय नियंत्रण की दो फोटो-स्टेट प्रतियां।
- (3) पैरा 14 (3) में उल्लिखित बोलियों का विवरण पत्र।
- (4) दो प्रतियों में सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षक नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, डी ई ए यूको बैंक बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली को एक प्रति और दूसरी प्रति अवर सचिव, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, आई ए सैवशन, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को भेजेंगे (अनुबंध-1 में निर्धारित अन्य ब्यौरे)।

संविदा पर आगे कार्रवाई तभी की जाएगी जब कि आयातक द्वारा वे सभी दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए गए हों।

प्राधिकार पत्र जारी करना :

17. यदि संविदा, दस्तावेज, प्राधिकार पत्र के और आयात लाइसेंस जारी करने के आवेदन पूर्ण, पाए जाते हैं तो सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षक नियंत्रक, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), यूको बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली संविदा का अनुमोदन करेंगे और अनुबंध-2 के रूप में प्राधिकार पत्र जारी करेंगे।

भुगतान के तरीके :

18. भारत के आयातक के बैंक के नाम से प्राधिकार पत्र जारी करने के बाद पी के बैंक ० एम-10371 स्टाक-होम, स्वीडन में साख्य पत्र स्थापित किया जाएगा।

19. उस विदेशी बैंक का जिसके साथ-साथ पत्र स्थापित किया गया है, यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अपरक्राम्य पोत परिवहन दस्तावेजों 100% बीजक मूल्य तक के भुगतान की प्राप्ति के तथ्य को दर्शाते हुए संभरक से प्रमाणपत्र और सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षक नियंत्रक, यूको बैंक, बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 से उद्गम प्रमाण पत्र सहित वाणिज्यिक बीजक का एक सैट भेजेगा। (भारतीय बैंकर को लिए यह अति आवश्यक है कि स्थापित किए जाने वाले साख्यपत्र में इस आशय का प्रावधान शामिल करे)।

20. प्रेषण के बाद भारतीय आयातक का बैंक-प्रपत्र-“क” की एक अनतिरिक्त प्रति भरेगा और उसे सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षक नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग यूको बैंक बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली को भुगतान की की तिथि से 15 दिनों के भीतर प्राप्त बीजक, लदान बिल और ऊपर खण्ड-19 में उल्लिखित उद्गम प्रमाण-पत्र के साथ अपरक्राम्य पोत परिवहन दस्तावेज का एक सैट भेजेगा।

21. (1) ऊपर पैरा 19 और 20 में उल्लिखित दस्तावेजों के प्राप्त होने पर सीएएस एण्ड ए आयातकों और/या नई दिल्ली स्थित एम आई डी ए के माध्यम से नेशनल बैंक ऑफ स्वीडन अर्थात् पी के बैंक से आयातक द्वारा दी गई आपूर्ति की प्रतिपूर्ति का दावा करेगा। इसकी सूचना वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को भी भेजेंगे।

(2) भारतीय आयातक और भारतीय बैंकर दोनों यह सुनिश्चित करेंगे कि अपेक्षित सूचना सही, पूर्ण और विशिष्ट शब्दों में संगत कालमों के सामने दी गई है।

(3) यह भी प्रपत्र-“क” पर भारतीय बैंकर के प्राधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर भी इसके कार्यालय की मोहर के साथ होंगे।

(4) वित्त मंत्रालय, सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षक नियंत्रक, यूको बैंक बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को शीघ्र प्रतिपूर्ति दस्तावेजों को भेजने में आयातक का ओर से कोई भी गलती गम्भीर रूप से ली जाएगी और मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को आयातक के नाम के सभी आयात लाइसेंस रद्द करने को कहा जाए। यदि किसी मामले में आयातक गलती दोहराता जाता है तो मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को उसका मामले की सफाई काली सूची में रखने के लिए की जाए। इसके अनतिरिक्त, आयातक आयात नियंत्रण अधिनियम, संचालित करने का विधि के अर्थात् दण्ड/मजरा का भागीदार होगा।

प्रतिदाय राशि :

22. यदि विदेशी संभरक या बीमाकर्ता से भारतीय आयातकों द्वारा कोई प्रतिदाय राशि प्राप्त की जाती है तो संबंधित ब्यौरों के साथ प्राप्त की गई धनराशियों को वर्गित करते हुए एक पूर्ण रिपोर्ट अनुबंध-3 में दिए गए प्रपत्र में सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षक नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यूको बैंक बिल्डिंग, नई दिल्ली-11000 को भेजी जानी चाहिए।

भारतीय आयातकों द्वारा वास्तविक भुगतानों की रिपोर्ट भेजना :

23. जब और जैसे ही भारतीय आयातकों द्वारा बाह्य संभरकों को संविदाओं के मुद्दे वास्तविक भुगतान कर दिए जाते हैं तो उसे निरपवाद रूप से इसकी रिपोर्ट सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यूको बैंक बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली

को भेजनी चाहिए। भुगतानों की रिपोर्ट भेजते समय आयातक को चाहिए कि वे भेजे गए/भेजे जा रहे प्रत्येक संविदा के मद्दे आयातित उपकरण के उद्देश्यों का संक्षेप में संकेत भी करें। ये रिपोर्ट वास्तविक भुगतान हो जाने के एक सप्ताह के भीतर ही सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यूको बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को भेज दी जानी चाहिए।

विविध :

24. आयातक को लाइसेंसों के समुपयोजन स्थिति को दर्शाते हुए अनुबन्ध-4 में एक तिमाही रिपोर्ट वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (आई ए अनुभाग) और सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षक नियंत्रक, यूको बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए।

25. यह समझ लेना चाहिए कि यदि कोई विवाद लाइसेंस-धारी और संभरक के बीच हो जाता है तो भारत सरकार की उस विवाद के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। भुगतान से पूर्व संभरक द्वारा पूर्ण की जाने वाली शर्तें जो उसे प्रभावी

की जा सकती है, आयातक को उन्हें संभरक को स्पष्ट कर देना चाहिए और विवाद के निपटान से संबद्ध प्रावधान संविदा में भी जोड़ दिया जाए।

26. वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, (आई ए सैक्शन) की पूर्व सहमति के बिना अनुमोदित संविदाएं रह नहीं की जानी चाहिए।

27. भारतीय आयातक को आयात लाइसेंस से संबंधित किसी एक या सभी मामलों के संबंध में और स्वीडन के प्राधिकारियों के साथ क्रेडिट समझौते के अन्तर्गत सभी दायित्वों को पूर्ण करने के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों, अनुदेशों या आदेशों का तुरन्त पालन करना होगा।

28. ऊपर खण्डों में निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार उल्लंघन करने पर आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अन्तर्गत आयातक या उसके बैंकों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाएगी।

अनुबन्ध-1

(दो प्रतियों में)

[पैरा 16(4)]

सेवा में,

मन्त्रि,
वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग,
आई ए अनुभाग, नार्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली।

द्वारा : सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), यूको बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।

विषय :—भारत-स्वीडन विकास सहयोग समझौता, 1987 के अन्तर्गत आयात।

महोदय,

उपर्युक्त समझौते के अन्तर्गत—

के

(माल अथवा सेवाओं का संक्षिप्त विवरण)

आयात के संबंध में हम निम्नलिखित ब्यौरे भेजते हैं :—

(क) आयातक का नाम तथा पता :

(ख) आयात लाइसेंस :

(1) संख्या

(2) तिथि

- (3) धनराशि
 (4) कब तक वैध
 (क) संविदा के लिए
 (ख) पोतलदान के लिए
 (ग) विदेशी संभरक का नाम तथा पता
 (घ) संविदा की तिथि

अथवा

आदेश के लिए संभरक के अन्तिम अनुमोदन पत्र की तिथि-----

- (ङ) आयात किए जाने वाले माल का संक्षिप्त विवरण
 (च) संविदा का मूल्य

जहाज पर निःशुल्क मूल्य

विदेशी मुद्रा में

समतुल्य भारतीय रुपये में

भाड़ा

बीमा

कुल-----

- (छ) संविदा में यथा निर्धारित संभरण की अनुसूचियों के आधार पर विभिन्न तिथियों जिनको उपकरण लदान किए जाएंगे अथवा सेवाएं निष्पादित की जाएंगी, प्रत्येक लदान अथवा निष्पादित सेवाओं का मूल्य आधारित होगा।

विदेशी मुद्रा में पोतलदान की मुद्रा

- (ज) वह तिथि जिसकी संविदा के अन्तर्गत भुगतान करने होंगे :—

तिथि

विदेशी मुद्रा में राशि

- (1) अग्रिम भुगतान के संबंध में
 (2) अन्य भुगतानों के संबंध में
 (3) यदि कोई हो तो भारतीय अभिकर्ता का कमीशन

- (झ) विदेशी मुद्रा में विनिमय में प्राधिकृत इस व्यापारी/बैंक का नाम और पता जिनके माध्यम से साख्यपत्र खोलने के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी।

- (ञ) उस विदेशी बैंकर का नाम और पूरा पता जिसके पास साख्यपत्र स्थापित किया जाएगा।

2. संविदा की 4 प्रतियां अथवा प्रत्येक आदेश तथा स्वीकृत पत्र तथा संशोधन (यदि कोई हो) की चार प्रमाणित प्रतियों तथा आयात लाइसेंस की दो फोटो स्टेट प्रतियां संलग्न की जाती है।

3. विदेशी संभरक का चुनाव अन्तर्राष्ट्रीय जांच पड़ताल के आधार पर किया गया है और प्राप्त किए गए आदेश का एक विवरण संलग्न है। माल स्वीडन मूल के हैं और विदेशी संभरक का माल के मूल उद्गम का प्रमाण-पत्र संलग्न है।

4. आप से अनुरोध किया जाता है कि भारत स्वीडन विकास सहयोग समझौता, 1987 के अन्तर्गत वित्त मंत्रालय पोषण के लिए संविदा अनुमोदित करा लें और उपर्युक्त संकेतित उनके बैंकर के माध्यम से संभरकों को भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करें।

भवदीय,

(लाइसेंसधारी)

अनुबन्ध-2

(कंडिका-17)

संख्या एफ
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
नई दिल्ली, दिनांक
प्राधिकार पत्र सं० _____

सेवा में,

(भारतीय बैंक)

विषय :- भारत-स्वीडन विकास सहयोग समझौता, 1987 के अन्तर्गत की गई

संविदा—सामान्य आयात/स्वीडन आयात सेगमेंट।

प्रिय महोदय,

सर्वश्री _____ की भारत-स्वीडन विकास सहयोग समझौता, 1987 के
(भारतीय आयातक)

अन्तर्गत जारी किए गए लाइसेंस संख्या _____
दिनांक _____ मूल्य _____

के मद्दे _____ एपए की धनराशि लागत-
बीमा-भाड़ा/लागत तथा भाड़ा के लिए _____ का संभरण
करने के लिए सर्वश्री _____ के साथ
(विदेशी संभरक)

संविदा कर ली है। संविदा की एक प्रति संलग्न की जाती है।

2. _____ की धनराशि में से _____
की धनराशि भारतीय मुद्रा में भारतीय अभिकर्ता के कमीशन के रूप में चुकाई जाती है इसलिए विदेशी मुद्रा में संभरक को चुकाई
जाने वाली धनराशि जो कि स्वीडन क्रेडिट में से वित्तयुक्त की जाएगी वह _____ की
धनराशि होगी।

3. आपको सहायता लेखा और लेखा परीक्षा नियंत्रक, यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को सूचना
देने हुए इस पत्र के जारी होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर _____
(विदेशी संभरक)

के नाम में उनके बैंकर, अर्थात् सर्वश्री _____
_____ के माध्यम से एक साखपत्र खोलने के लिए प्राधिकृत किया
जाता है।

4. साखपत्र खोलने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि भारतीय आयातक के पास वैध आयात लाइसेंस है।

5. मुद्रा विनियम नियंत्रण नियंत्रण पुस्तक के अध्याय-13-ख-8 के अनुसार आपके लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा
कि साख पत्र के समाप्त होने की तिथि सम्बंध आयात लाइसेंस में यथा विनिर्दिष्ट पोतलवान के लिए अन्तिम तिथि के बाद 75
दिनांक से अधिक की नहीं है।

6. साख पत्र में यह भी व्यवस्था होगी कि सर्वश्री—

(विदेशी बैंकर)

अपरक्राम्य पोतलवान दस्तावेजों के एक सेट को इस संबंध में सीधे ही सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजेगा कि प्रत्येक भुगतान पूरा कर लिया गया है।

7. आप से अनुरोध है कि भुगतान के तुरन्त बाद ही भारत-स्वीडन विकास सहयोग समझौता 1987 के अन्तर्गत आयात करने के लिए लाइसेंस शर्तों की कंडिका 20 के अनुसार विदेशी संभरक को प्रेषित धनराशि का विवरण दर्शाते हुए प्रपत्र "क-1" की अतिरिक्त प्रति सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजें।

8. कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दें।

भवदीय

वरिष्ठ लेखा अधिकारी

1. प्रति रिजर्व बैंक आफ इंडिया, मुद्रा विनियम नियंत्रण विभाग को प्रेषित

2. बिना अनुलग्नक के प्रति निम्नलिखित को प्रेषित :—

1.
(भारतीय आयातक)2.
(विदेशी संभरक)3.
(विदेशी बैंक)

यह अनुरोध है कि प्रत्येक भुगतान पर भुगतान बीजक के साथ पोत परिवहन तथा अन्य दस्तावेजों (अपरक्राम्य) का एक सेट सीधे ही सहायक लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली (भारत) को भेजा जाए।

3. संविधा तथा आयात लाइसेंस की एक प्रति के साथ अवर सचिव, वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग (आइ ए अनुभाग)

4. रिजर्व बैंक आफ इंडिया, मुद्रा विनियम नियंत्रण विभाग बम्बई

वरिष्ठ लेखा अधिकारी

अनुसूद्ध-3

(पैरा-22)

आयातों के सम्बन्ध में लदान कम होने, हानियों आदि के लिए दावों को तय करने हेतु विदेशी सम्भरकों/पोतवणिकों/बीमा-कर्माओं से धन प्रतिदाय को दर्शाने वाली रिपोर्टें।

1. भारतीय आयातक का नाम _____
2. आयात लाइसेंस की संख्या और तिथि _____
3. आयात लाइसेंस का मूल्य _____
4. प्राधिकार पत्र की संख्या और तिथि _____
5. प्राप्त प्रतिदाय राशि _____
6. स्वरूप एवं प्रतिदाय राशि (संक्षिप्त विवरण दें) _____
7. सम्बन्धित प्रपत्र "क1" का वह संदर्भ जिस के अधीन विदेशी सम्भरकों को शुरू में भुगतान किया गया था (भारतीय बैंकर का नाम और वित्त मंत्रालय को प्रपत्र "क" भेजते हुए उनके पत्र सं० और तिथि को निर्दिष्ट करें) _____
8. क्या प्राप्त की गई प्रतिदाय राशि माल के प्रतिस्थापन के लिए उपयोग की जानी है या नहीं, यदि नहीं तो यह पुष्टि करें कि धनराशि विदेशी मुद्रा के आन्तरिक प्रेषण द्वारा वास्तविक रूप में प्राप्त हो गई है और उसे रुपये में भुना लिया गया है
9. अन्य और कोई आवश्यक व्यौरे

(आयातक फर्म के प्राधिकृत
अधिकारी के हस्ताक्षर)

सेवा में

सहायता लेखा और लेखा परीक्षा के नियंत्रक
वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)
यूको बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग,
नई दिल्ली।

अनुबन्ध-4

(पैरा-24)

स्वीडन क्रेडिट के अधीन उपयोग की तिमाही रिपोर्ट बनाने वाला विवरण

1. आयातक का नाम
2. आयात लाइसेंस की संख्या और तिथि
3. आयात लाइसेंस का मूल्य
4. प्राधिकार पत्र की संख्या और तिथि
5. प्राधिकार पत्र की धनराशि
6. प्राधिकार पत्र की वैधता की तिथि
7. दिए गए आदेश का मूल्य
8. तिमाही के दौरान प्रयुक्त धनराशि
9. अब तक प्रयुक्त कुल धनराशि
10. सरकारी लेखों में जमा की गई कुल राशि
11. उत्तरोत्तर तिमाहियों के दौरान किए जाने वाले सम्भावित भुगतान (तिमाही बार आकड़ें दें)
12. अभ्यर्पण, यदि कोई हो।

स्वीडन क्रो: _____

स्वीडन क्रो: _____

MINISTRY OF COMMERCE

Import Trade Control

PUBLIC NOTICE NO. 228 ITC (PN) 85-88

New Delhi, the 17th November, 1987.

Subject :—Conditions for licensing Private Sector and Public Sector Imports under the Indo-Swedish Development Cooperation Agreement, 1987-89.

Issued from File No. IPC/23 (39) 85-88 :—The terms and conditions governing imports under the Indo-Swedish Development Cooperation Agreement, 1987-89 as given in Appendix to this Public Notice are notified for information.

Sd/-

R. L. MISRA, Chief Controller of Imports and Exports.

R. K. DHAWAN, Dy. Chief Controller of Imports and Exports.

Appendix to the Ministry of Commerce Public Notice No. 228. ITC (PN) 85-88 dt. 17-11-1987

PREAMBLE

Swedish Assistance under the Indo-Swedish Development Cooperation Agreement (1987), consists of the segment Import from Swedish which can be effected or services obtained only from Sweden i.e. the goods must be manufactured in Sweden.

IMPORT LICENCE

1. The import licence will be issued on CIF basis with the initial validity period of four months for contracting and twelve months for completion of shipments as well as payments. All shipments must be completed within a month of the date of expiry of the licence.

2. Each import licence will bear a superscription. "Indo-Swedish Development Cooperation Agreement, 1987—Imports from Sweden". The suffixes in the licence code classification number will be "SW". These will also be repeated in the letter from the Chief Controller of Imports & Exports forwarding the Import Licence.

3. Within a fortnight of the receipt of the import licence, the importer should intimate to the Department of Economic Affairs (IA Section) the fact of receipt of the Import Licence, indicating the number, date and value of the import licence and likely date by which the contract document be furnished.

4. The condition regarding contracting shall not be DEEMED TO HAVE BEEN COMPLIED WITH UNLESS complete contract documents, as provided in para 16 below, are furnished within the stipulated period of four months.

5. Where this stipulation is not complied with within four months, the import licence will be deemed to have become invalid.

6. The import licence may, however, be revalidated on an application by the party, wherein the reasons for not complying with the requirement in time should be stated. The request for revalidation would be considered by the licensing authority on merits and the licence will be revalidated for contracting for a further period not exceeding two months. Any revalidation beyond this period will require the prior approval of the Department of Economic Affairs (I.A. Section).

CONTRACTING

7. A contract will normally comprise an Agreement signed by both the parties viz. the Indian importer and the foreign supplier or it may comprise the order placed by the Indian importer and the letter of acceptance by the foreign supplier thereof in unequivocal terms. Orders on Indian Agents of the Overseas Suppliers and/or order confirmation by such Indian Agents are not acceptable.

8. A contract comprising a series of correspondence between the two parties frequently amending/ revising the various provisions will not be generally accepted. In such cases, it is necessary to prepare a final document including therein the terms agreed to and signed as such by both the parties.

9. Normally, one contract, on the basis of firm prices, has to be entered into with the foreign supplier for the whole amount of the licence. However, if, for special reasons, conclusion of more than one contract becomes necessary, prior permission of the Department of Economic Affairs should be obtained, giving reasons for doing so.

TERMS OF CONTRACT

General :

10. The importers in the private sector are required to place the contracts on C.I.F. or C & F basis. They should clearly indicate the F. O. B. price, insurance charges and freight separately.

Contract must be entered only on C & F basis, by a Government agency or a public sector undertaking.

If any importer desires to enter into a contract on F. O. B. basis, the party should seek prior

permission of the Department of Economic Affairs, (IA Section), Ministry of Finance, New Delhi giving reasons for doing so.

11. If any commission is to be paid to the Indian agents of the foreign supplier, it will be shown separately from the value of the contract. The Indian agent's commission will be paid in India in rupees but will be set off against the total value of the import licence.

12. The value of the contract should be expressed in the currency in which the payment is to be made to the foreign supplier. The conversion of these amounts into Rupees shall be made at the rates of exchange notified by the Department of Revenue (Customs) under Section 15 of the Customs Act, 1962 and prevailing on the date of issue of the import licence.

Value Limits of Contracts :

13. The value of each contract should not be less than amount equivalent to Rupees seventy-five thousand (Rs. 75,000).

Origin of Goods :

14. (i) In the case of imports from Sweden referred to in the preamble, the goods should be manufactured in Sweden or the services to be rendered should be of Swedish origin. A stipulation as to the Swedish manufacturing of goods or Swedish origin of services should be incorporated in the contract.

(ii) The licensee should, while submitting the contract documents referred to in para 16 (iii) below, furnish a statement of bids received and the reasons for selecting the particular supplier and goods.

Shipments :

15. The Contract should spell out delivery/shipment schedules in specific terms indicating the month of each such delivery/shipment, as closely as possible.

Any subsequent deviation from the shipping schedule should be promptly notified to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, IA Section, North Block, New Delhi.

DETAILS OF CONTRACT DOCUMENTS REQUIRED TO BE SUBMITTED.

16. Within 20 days of the conclusion of the contract, the importer should send a letter accompanied by the following documents to the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Deptt.

of Economic Affairs, U.C.O. Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

- (i) Four certified copies of the contract and any further amendments duly executed in English language and signed by both the Indian importer and the foreign supplier.
- (ii) Two photostat copies of the import licence (Exchange Control Copy) valid for contracting on the date of execution of the contract/acceptance by foreign supplier of the order placed by the importer.
- (iii) Statement of bids mentioned in para 14(ii).
- (iv) Other particulars stipulated in Annexure I (2 copies—one to Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, DEA, UCO Bank Bldg., Parliament Street, New Delhi and other to the Under Secretary, Ministry of Finance, Deptt. of Economic Affairs, IA Section, North Block, New Delhi).

The contract will be processed only after all these documents have been furnished by the importer.

Issue of Letter of Authority :

17. If the contract documents, the request for issue of letter of authorisation and the import licence are found to be in order the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, (Department of Economic Affairs), UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi will approve the contract and issue the Letter of Authority in the form at Annexure II.

Method of Payment :

18. After the issue of Letter of Authority in favour of the importer's bank in India, a Letter of Credit will be established on the PK BANKEN, S-10371 Stockholm, Sweden.

19. It will be the responsibility of the Swedish Banker with whom the Letter of Credit has been established to forward one set of non-negotiable shipping documents, commercial invoice bearing a certificate from the supplier indicating the fact of receipt of payments amounting to 100% of the invoice value and the certificate of origin to the Controller of Aid Accounts and Audit, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110 001. (It is absolutely necessary for the Indian banker to include a provision to this effect in the Letter of Credit to be established).

20. After the remittance is made, the Indian Importers' bank shall fill in an additional copy of Form 'A' and forward the same to the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building,

Parliament Street, New Delhi within 15 days from the date of payment together with one set of non-negotiable shipping documents comprising of Receipted Invoice, Bill of Lading and Certificate of Origin referred to in Section 19 above.

21. (i) On receipt of the documents mentioned in para 19 and 20 above, the CAA&A will claim reimbursement of the cost of imports and/or Supplies paid by the importer from the National Bank of Sweden i.e. P. K. BANKEN through the SIDA office at New Delhi under intimation to IA Section, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, North Block, New Delhi.

(ii) Both the Indian importer and the Indian banker will ensure that all the requisite information is given correctly, fully and in specific terms against the relevant columns.

(iii) Form A will further bear the signature of the authorised officer of the Indian banker and stamped with its official seal.

(iv) Any omission on the part of the importer to send reimbursement documents promptly to the Ministry of Finance, Controller of Aid Accounts & Audit, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110 001 will be viewed seriously and the CCI&E may be asked to suspend all import licences in the name of the importer. In case the importer persists in his default, his case may be recommended to the CCI&E for being blacklisted. The importer will in addition be liable to penalties/punishment under the law governing Import Control Act.

Refunds :

22. If any refunds are received by the Indian importers from the foreign supplier or the insurer, a full report showing the amounts received, together with relevant particulars, should be sent to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110 001 in the form given in Annexure III.

Reporting of Actual Payments, etc. by the Indian Importers :

23. The Indian importers should invariably report to the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs,

UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi as and when actual payments against individual contracts are made by them to the overseas suppliers. While reporting the payments, the importer should also indicate briefly the purposes to which the equipment imported against each contract has been/is being put to. These reports should be sent to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance (DEA), UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi within one week of the actual payments having been made. Controller of Aid Accounts and Audit will reflect these reports in their Quarterly statements of claims made and reimbursements received to be submitted by them to Department of Economic Affairs (IA Section).

MISCELLANEOUS

24. The importer should furnish a quarterly report as in Annexure IV showing the utilisation status of the licences to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (IA Section) and to the controller of Aid Accounts and Audit, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

25. It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any, that may arise between the licensee and the supplier. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment could be effected to him must be clearly spelt out to the supplier by the importer and a provision dealing with settlement of disputes may be included in the contract itself.

26. Approved contracts should not be cancelled without prior concurrence of the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (IA Section).

27. The licensee shall promptly comply with any directions, instructions, or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to import licence and for meeting all obligations under Swedish Government Credit.

28. Any breach of violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action against the importer or its bankers under the Imports and Exports (Control) Act.

Annexure—1

(in duplicate)

[Para 16 (iv)]

To

The Secretary,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
I.A. Section, North Block,
New Delhi.

Through: Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance (DEA) UCO Bank Bldg., Parl. Street, New Delhi.

Subject : Indo-Swedish Development Cooperation Agreement, 1987—Import under

Sir,

In connection with the import of _____

(Short description of the goods and services)

under the above Agreement, will be furnish the following particulars:-

(a) Name and address of Importer

(b) Import Licence :

(i) Number

(ii) Date

(iii) Amount

(iv) Valid upto

(a) for contracting

(b) for shipment

(c) Number and address of the foreign supplier:

(d) Date of the contract :

or

Date of suppliers' final letter of acceptance of the order

(e) Short description of the goods to be imported:

In foreign currency In equivalent Indian Rupees

(f) Value of the contract:

F.O.B. Price :

Freight:

Insurance:

Total:

Date Value of shipment
in Foreign currency

- (g) The difference dates on which the equipment will be shipped or services performed, the value of each shipment, or service performed, based on the delivery schedules as stipulated in the contract.

Date	Amount in foregin currency
------	----------------------------

- (h) The date on which payments under the contract will fall due
- (i) in respect of advance payment
 - (ii) other payments
 - (iii) Indian Agent's Commission, if any ?
- (i) Name and full address of the Indian dealer/bank authorised in foreign exchange through whom arrangements for opening a letter of credit will be made:
- (j) Name and full address of the foreign banker with whom the letter of credit will be established:

2. Four certified copies of the contract (or four copies each of the order and the letter of acceptance and of the amendment (if any) and two photostat copies of the import licence are enclosed.

3. The selection of the foreign supplier has been made on the basis of international enquiry and a statement of the orders received is enclosed. The goods are of Swedish Origin and a certificate of the origin of goods from the foreign supplier is attached.

4. You are requested to approve the contract for financing under the Indo-Swedish Development Cooperation Agreement, 1987 and issue authorisation for payment to the suppliers through their bankers, mentioned above.

Your faithfully,

(Licensee)

ANNEXURE-II

(Para 17)

No. F

Government of India
 Ministry of Finance
 Department of Economic Affairs
 (Controller of Aid Accounts & Audit)
 New Delhi the
 LETTER OF AUTHORITY NO. _____

To.

(Indian Banker)

Subject:- Contract entered under Indo-Swedish Development Cooperation Agreement. 1987-General Imports/
 Swedish Import Segment.

Dear Sirs,

Messrs. _____

(Indian Importer)

have entered into a contract with Messrs. _____

(Foreign supplier)

_____for the supply of _____

_____for the amount of _____

CIF/C&F under the Indo-Swedish Development Agreement, 1987 against Licence No. _____

_____dated _____

_____issued there under for the

value of Rs. _____A copy of the contract is enclosed.

2. Out of the above amount of _____an amount of _____is
 to be paid as Indian Agent's Commission in Indian currency. The sum to be paid to the supplier in foreign currency
 which will be financed out of the Swedish assistance will be therefore amount to _____

3. You are authorised to open a letter of credit for _____in favour of
 Messrs. _____

(Foreign supplier.

through their bankers, viz., Messrs. _____

(foreign banker)

within a period of thirty days from the date of this letter under intimation to the Controller of Aid Accounts & Audit,
 UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

4. Before opening the Letter of Credit, it may please be ensured that the Indian Importer is in possession of a
 valid import licence.

5. In terms of Chapter 13 B-8 of the Exchange Control Manual, you are required to ensure that the date of
 the expiry of Letter of Credit is not later than seventy five (75) days after the final date for shipment stated in the
 relative import licence.

6. The letter of Credit will also provide the Messrs. _____

(foreign banker)

will forwarded directly to the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi, one set of non-negotiable shipping documents as each payment is made.

7. You are also requested to forward to the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi one additional copy of the Form 'A1' showing particulars of remittances made to the foreign supplier in terms of section 20-of the Licensing Condition for imports under Indo-Swedish Development Cooperation Agreement, 1987 as soon as the payments are made.

8. Receipt of this letter may please be acknowledged .

Yours faithfully,

Senior Accounts Officer

1. Copy forwarded to Reserve Bank of India, Exchange Control Department, _____

2. Copy without enclosures forwarded to:—

i. _____
(Indian importer)

ii. _____
(Foreign Supplier)

iii. _____
(Foreign bank)

It is requested that on each payment, one set of shipping, and other documents (non-negotiable) alongwith payment advice may be forwarded direct to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi (INDIA).

iv. Under Secy, Ministry of Finance, Deptt. of Economic Affairs, (1A Section) with a copy of the contract and that of the import licence.

v. Reserve Bank of India, Exchange Control Department Bombay.

Senior Accounts Officer.

ANNEXURE-III

(Para 22)

REPORT SHOWING DETAILS OF REFUNDS FROM FOREIGN SUPPLIERS/SHIPPERS/INSURERS TOWARDS SETTLEMENT OF CLAIMS FOR SHORT LANDINGS, DAMAGES, ETC.) IN RESPECT OF IMPORTS.

1. Name of the Indian Importer.
2. No. and date of import licence.
3. Value of the import licence.
4. No. and date of Letter of Authority.
5. Amount of refund received.
6. Nature and refund.
(give brief details)
7. Reference to the relative Forms 'A1' under which payment was made initially to the foreign suppliers (indicate name of the Indian banker and reference to their letter No. and date, forwarding form 'A' to Ministry of Finance).
8. Whether or not refunds received are to be utilised for replacement of goods; if not, confirm that amount has been actually received by inward remittance of foreign exchange and encashed into rupees.
9. Any other necessary particulars.

(Signature of the Authorised
Officer of the Importing Firm).

To

The Controller of Aid Accounts and Audit,
Ministry of Finance (Deptt. of Economic Affairs),
UCO Bank Building, Parliament Street,
New Delhi.

ANNEXURE-IV

(Para 24)

STATEMENT SHOWING QUARTERLY REPORT ON UTILISATION UNDER SWEDISH CREDIT :

1. Name of Importer.
2. No. and Date of import licence.
3. Value of import licence.
4. Letter of Authority No. and date.
5. Amount of Letter of Authority.
6. Date of validity of Letter of Authority.
7. Value of orders placed.
8. Amount utilised during the quarter Sw Kr.
9. Total amount utilised so far Sw. Kr. _____
10. Total amount deposited into Government Account. |
11. Payment expected to be made during the subsequent quarters
(give figures-quarter-wise)
12. Surrenders, if any.